क्या भारतीय चुनावों में नीतियों का कुछ मतलब है?

Do Policies Matter in Indian Elections?

तारिक थैचिल

Tariq Thachil
April 26, 2010

2009 में हुए हाल ही के राष्ट्रीय चुनावों के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारी विजय के कारणों की समीक्षा करते हुए कई सिद्धांत उभरकर सामने आए. इन सिद्धांतों में एक था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी और उनके बेटे राहुल गाँधी के रूप में कांग्रेस नेतृत्व का व्यक्तिगत कौशल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख दावेदारों की अंदरूनी गुटबंदी. दोनों ही व्याख्याएँ बिल्कुल असंतोषजनक हैं, क्योंकि वे पूरी तरह निराधार हैं, तर्कों से परे हैं और उन्हें सही सिद्ध नहीं किया जा सकता. तीसरी व्याख्या सटीक लगती है और वह है कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के शासनकाल में चलाए गए कुछ लोकप्रिय सामाजिक कल्याण संबंधी नीति के कार्यक्रम. खास तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के नाम से यूपीए द्वारा रोज़गार सुरक्षा देने के जो प्रयास किए गए उसके कारण और कृषि ऋण की बड़ी रकम को माफ़ कर देने के कारण ही कांग्रेस को फिर से चुनाव में भारी जीत मिली.क्या सचमुच ही यह ऐसा प्रकरण है जिससे भारतीय लोकतंत्र की नीतियों के विकास-क्रम को समझा जा सकता है?

नरेगा जैसी नीतियों के महत्व पर बल देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवहार में मतदान के लिए इस प्रकार के मामले कितने अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. इस प्रकार के तर्क से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दल अब मतदाताओं, विशेषकर गरीब मतदाताओं के वोट पाने के लिए राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और स्थानीय उच्च वर्ग के कुछ लोगों के संरक्षण पर निर्भर नहीं रह सकते. आज़ादी के बाद के पहले दो दशकों में लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभुत्व के कारणों को इस प्रकार की प्रणाली की पूर्णता के रूप में समझा जाता था. चुनावों में कांग्रेस को चुनौती देकर उभरे नए दलों ने भी बिल्डिंग सपोर्ट की इस पद्धति को चुनौती नहीं दी. इसके बजाय भारतीय समाज के विशेष वर्गों के लिए मिली-जुली विचारधारा की अपील के कारण कांग्रेस के समान उन्होंने भी विशेष जातिगत समुदायों के भीतर (जैसे भाजपा ने उच्च वर्ग के भीतर और बहुजन समाज पार्टी ने निम्न वर्ग के भीतर) अपने संरक्षण की व्यवस्था कर ली.

इनमें जिन महत्वपूर्ण दलों का उल्लेख नहीं है वे हैं केरल के वामदल. इन्हें इस विश्लेषण में अपवाद माना जा सकता है.वास्तव में भारतीय दलों की चुनावी सफलता के स्रोत के रूप में वास्तविक *सामाजिक नीति का लाभ* इन्हीं वामदलों को मिला है. इशू-आधारित राजनीति के वर्चस्व का परिणाम यह हुआ है कि राजनीति के उच्चपदस्थ लोगों को भावी समर्थन प्राप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक सेवा को आधार बनाने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता. इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक नीतिगत विषयों पर भारत का खर्च राष्ट्रीय आय के प्रतिशत और प्रति व्यक्ति खर्च दोनों पर ही पूर्व और दक्षिण पूर्वेशिया की तुलना में भी कम रहा है. 1990 के दशक में भी जब

भारत की सकल आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो रहा था तो भी शिक्षा परGDP का अनुपात 3 और 4 के बीच ही अटका रहा था. यह अनुपात युनेस्को द्वारा अनुशंसित 6 प्रतिशत के मानदंड से काफ़ी कम रहा है. इसकी तुलना में पड़ोसी देश मलेशिया ने उसी अवधि में अपनी वचनबद्धता 4 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत GDP कर दी है. स्वास्थ्य की देखभाल पर तो खर्च बिल्कुल ही नगण्य रहा है और यह 1 प्रतिशत GDP से कम पर ही स्थिर बना हुआ है.

ऐसी पृष्ठभूमि में यह क्रांतिकारी बात है कि इशू और नीति संबंधी कार्यपरिणामों का विचार न केवल अपना महत्व रखता है, बल्कि राष्ट्रीय चुनाव के परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है. राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार 2009 का परिणाम एक ऐसी "कार्यक्रममूलक राजनीति" के उदय का संकेत है जिसे सफल बनाया ही जाना चाहिए और राजनीतिक दलों को नरेगा जैसी प्रत्यक्ष सार्वजनिक नीतियों को लागू करना ही होगा. शायद पहली बार *"आम आदमी"* की ज़रूरतें चुनावी भाषणबाजी से अधिक कारगर सिद्ध हुईं और यही वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के लोकतंत्रीकरण का संकेत है. लोकप्रिय प्रेस का यही दावा है. कुछ शंकालु लोग निश्चय ही उन समस्याओं को गिनाएँगे जो इस प्रकार के चलताऊ सामान्यीकरण के भीतर निहित हैं और जिन्हें बड़ी सरलता से राष्ट्रीय चुनावों के सार के रूप में सामने रखा जा सकता है. 2004 में हुए पिछले राष्ट्रीय चुनावों में हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पराजय का कारण "इंडिया शाइनिंग" के अभियान को बताया गया था, क्योंकि इसमें निम्न जाति के मतदाताओं को देश के तीव्र आर्थिक विकास से अलग रखा गया था..परंतु बाद के शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा की पराजय के कारणों में गरीबों के मिले-जुले आक्रोश का कोई स्थान नहीं था. वस्तुतः राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (NES) के परिणामों के अनुसार भाजपा ने वस्तुतः 2004 में हुए विभिन्न राज्यों के चुनावों में निम्न जातियों के समर्थन से भारी सफलताएँ प्राप्त की थीं.

आरंभिक प्रमाणों के रूप में कुछ मिली-जुली प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगता था कि 2009 में कांग्रेस की सफलता का आधार सामाजिक नीतियाँ थीं, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे दावे की प्रामाणिकता का मूल्यांकन व्यावहारिक स्तर पर किया जाए. दिल्ली में स्थित विकासशील समाज के अध्ययन केंद्र द्वारा किए गए 2009 के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (NES) के आँकड़ों से पता चलता है कि दस में से छह ग्रामीण गरीब मतदाताओं को यूपीए की दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं (नरेगा और कृषि ऋणों की माफ़ी) की जानकारी थी. फिर भी नरेगा जैसे व्यापक कार्यक्रम के लाभग्राहियों की संख्या बहुत कम थी. राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (NES) से संकेत मिलता है कि केवल 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीब मतदाताओं को नरेगा का लाभ मिला था और केवल 25 प्रतिशत को ही कृषि ऋण की माफ़ी का लाभ मिला था. इसलिए यह तर्क व्यावहारिक लगता है कि लाभग्राही मतदाताओं की संख्या इतनी अधिक नहीं थी कि वे एकमुश्त रूप में ही राष्ट्रीय चुनावों के परिणाम को प्रभावित कर सकें.

साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि भारत की पहली और बाद की चुनाव प्रणाली के कारण मतों का छोटा-सा अंश भी सीटों में भारी हेर-फेर कर सकता है. उदाहरण के लिए राष्ट्रीय संसद में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या में जबर्दस्त इजाफ़ा हुआ और 2004 और 2009 के बीच यह संख्या बढ़कर इकसठ हो गई और यह बढ़ोतरी भी वोट शेयर में मात्र 2.1 प्रतिशत की वृद्धि के कारण ही हुई है.

जेम्स मैनोर द्वारा हाल ही में किए गए राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (NES) के आँकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया है कि कांग्रेस ने इन योजनाओं के कारण अपने राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले विशेषकर भाजपा के मुकाबले भारी चुनावी जीत दर्ज की है. यहाँ तक कि अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच भी इससे सीट शेयर गैर-आनुपातिक रूप में परिणामकारी सिद्ध हो सकता है और इस प्रकार अंतिम चुनाव परिणामों पर इसका भारी प्रभाव पड़ सकता है.

मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इन योजनाओं के लाभग्राहियों और कांग्रेस समर्थन के अंतः संबंध यह प्रमाणित करने के लिए काफ़ी नहीं हैं कि मतदान पर इनका थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ता है. I इस संबंध को पूरा करने के लिए कई सवालों के जवाब देने होंगेः मतदाता इन नीतियों का श्रेय केंद्र सरकार को देते हैं या राज्य सरकार को,किसी दल विशेष को या किसी व्यक्तिविशेष राजनीतिज्ञ को, जटिलता के इन उलझे हुए स्तरों को सुलझाने के लिए अकादमीय स्तर के भावी शोध की आवश्यक्ता होगी. इसके अलावा यदि सामाजिक नीतियाँ चुनावी परिणामों पर असर डालती हैं तो भी इसका यह गलत मतलब नहीं निकाल लिया जाना चाहिए कि व्यक्तिनिष्ठ राजनीति का अंत होने वाला है उदाहरण के लिए राजनैतिक दृष्टि से क्षेत्रीय व्यक्तियों की पहचान का असर भी बढ़ता जा रहा है राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (NES) के अधिकांश उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि राष्ट्र से भी ऊपर क्षेत्र के प्रति निष्ठा अधिक आवश्यक है. चुनाव में कांग्रेस की भारी सफलता के बावजूद क्षेत्रीय दलों का शेयर कम नहीं हुआ है. इन दलों ने कुल मतों में से लगभग 30 प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं. योगेंद्र यादव और सुभाष पल्सीकर ने 2009 के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (NES) के अपने विश्लेषण में यह टिप्पणी की है कि भारत के उत्तरी राज्यों में जातिगत समुदाय के आधार पर मतदान का चलन अभी-भी है.

इसप्रकार व्यक्तिनिष्ठ राजनीति की समाप्ति और इशू-आधारित चुनावों के श्रीगणेश के बड़े-बड़े दावे करने के बजाय 2009 के चुनाव-परिणामों से यह संकेत लिया जाना चाहिए कि व्यक्तिनिष्ठ राजनीति और इशू-आधारित चुनावों के बीच द्विभाजन अभी अपने-आप में बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है. आर्थिक हित हमेशा ही जातिगत विभाजन से अलग नहीं होते. जहाँ जाति और वर्ग के सरोकार आपस में मिलते हैं वहाँ पर वस्तुतः इशू-आधारित मतदान का महत्व एक दूसरे को अतिच्छादित कर लेता है और व्यक्तिगत पहचान पर आधारित सामाजिक विभाजन में समाहित हो जाता है. इस सम्मिलन से जाति-आधारित मतदान की प्रवृत्ति की निरंतरता बनी रहती है,लेकिन सार्वजनिक नीति के निष्पादन से यह संकेत भी मिलता है कि इसमें नए हितों की अभिप्रेरणा भी निहित होती है. यदि सचमुच ऐसा होता है तो कुछ भारतीय बदलाव के साथ कार्यक्रममूलक राजनीति का उदय होने जा रहा है और यह प्रवृत्ति निश्चय ही भविष्य में दर्शनीय रहेगी.

तारिक थैचिल संप्रति येल विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्र अध्ययन के मैकमिलन केंद्र में पोस्ट डॉक्टरेट फ़ैलो हैं. वर्ष 2010-11*में वे राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे.*

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार

<malhotravk@hotmail.com>